Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 4, Issue - 7, July - 2021
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.871
Received on : 12/07/2021 Accepted on : 27/07/2021 Publication Date: 31/07/2021

कोरोना और सामाजिक संकट : एक विश्लेषण

नीरज कुमार राय
सहायक प्रोफेसर, राजकीय महिला महाविद्यालय, ढिंढुई,पट्टी, प्रतापगढ़
Email - dr.nkrbhu@gmail.com

सारांश : कोरोना संकट और लॉकडाउन ने समाज मे गंभीर समस्या पैदा की हैं। कोरोना के कारण आमजन के सामान्य रोजगार छीन गए हैं बेरोजगारों की संख्या मे भारी मात्रा मे वृद्धि की हैं। मजदूर वर्ग और श्रमिक वर्ग जो रोज प्रतिदिन काम करके आय अर्जित करता हैं वह आज निराश हैं, किसान भी हताश हैं। प्रारम्भिक स्तर पर कोरोना महामारी के निदान का वैज्ञानिक उपाय न होने के कारण वैश्विक स्तर संकट पैदा किया। प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैं।

मुख्य शब्द : कोरोना संकट, लाकडाउन, दैनिक मजदूरी, कारखाने, बेरोजगारी।

चीन से भारत मे कोरोना के फैलने की पुष्टि **30** जनवरी **2020** को हुयी। **30** जनवरी से **3** फरवरी के बीच केरल में सिर्फ़ तीन केस सामने आए थे। ये सभी वो छात्र थे जो वुहान से लौटे थे। कोरोना के मामलों का अगला चरण मार्च में शुरू हुआ जिसमें वो मरीज़ भी शामिल थे जो दुनिया के दूसरे हिस्सों से यात्रा करके लौटे थे। बचाव हेतु संकट को रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना निषेध किया गया है। सभी परिवहन सेवाओं - सड़क, वायु, और रेल को निलंबित किया गया है हालांकि आग, पुलिस, जरूरी सामान और आपातकालीन सेवाओं का उपयोग किया जा सकेगा। शैक्षिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आतिथ्य सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया हैं। खाद्य दुकानें, बैंक और एटीएम, पेट्रोल पंप, अन्य आवश्यक वस्तुएं और उनके विनिर्माण जैसी सेवाओं को छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि जो व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे उन्हें एक साल तक की जेल भी की जा सकती है। इस दौरान लगातार प्रधानमंत्री सामाजिक दुरी और अलगाव के माध्यम से समस्या से निपटने हेतु अपील कर रहे हैं।

सरकार ने पूरे देश में जिस लॉकडाउन का एलान किया है, उसे साम्राज्यवाद के दौर के क़ानून एपिडेमिक डिज़ीज़ एक्ट के तहत लगाया गया है। ये क़ानून आज से **123** साल पहले यानी वर्ष **1897** में बना था। इसके अलावा सरकार ने अपनी घोषणा को क़ानूनी जामा पहनाने के लिए वर्ष **2005** में बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन क़ानून की भी मदद ली है। भारत में नए कोरोना वायरस की वजह से फैली कोविड-**19** की महामारी ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। इससे न केवल हमारे देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की ख़ामियां उजागर हो गई हैं। बल्कि जोखिम से जुड़े संवाद और संकट के प्रबंधन से जुड़े क़ानूनी ढांचे की कमियों को भी सामने ला दिया है। लेकिन इस कोरोना संकट ने आमजन के सामने एक गंभीर संकट पैदा किया हैं और इससे सबसे ज्यादा परेशान तबका किसान ,श्रमिक ,मजदूर ,छोटे कर्मचारी ,छोटे उद्योग धंधे और दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले लोग हैं जो रोज सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं।अगर ये सुबह ना कमाए तो शाम को खाना भी नसीब नहीं होगा।

कोरोना संकट एक ऐसी महामारी हैं जिसने भारतीय सामाजिक आधार को ही ध्वस्त करने का पूरा मन बना लिया हैं। लाकडाउन के कारण सबसे बुरी स्थिति किसानो की हैं। लाकडाउन के चलते अभी भी भोजन का संकट इसलिए नहीं उत्पन्न हुआ की हमरे पास खाद्दान का बड़ा भंडार रखा हुआ है। लेकिन जब सम्पूर्ण अर्थव्यस्था ,बाजार और कारखाने बंद हैं ,समाज का प्रत्येक इंसान अपने और अपने लोगो को बचाने मे लगा हुआ हैं उस समय किसान की चिंता अपने फसलों को बचाने की हैं। जिस समय प्रतिबन्ध लागु हुआ उस समय वही किसान के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योकि अधिकतर फसलों की कटाई का यही समय हैं और इसी समय अधिक मजदूरों और कटाई मे लगे श्रमिकों की जरूरत पड़ती हैं जो प्रतिबंधों के चलते मिल नहीं पा रहे हैं। देश के अनेक हिस्सों मे आलू के किसानो को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा हैं। कई जगहों पर फसलों को खेत मे छोड़ना पड़ा हैं। कर्नाटक मे टमाटर के किसानो को काफी नुकसान उठाना पड़ा हैं। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र से आम की खेप बाजार मे आने को तैयार हैं लेकिन उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण ये अभी बाजार से दूर हैं।अंगूर किसानो को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा हैं। दक्षिण मे मिर्च ,गुजरात मे जीरा, सौफ ,धनिए की फसल कट चुकी हैं लेकिन मार्केटिंग का इन्तजार हैं। एक बड़ा पहलु दूध उत्पादक किसानो का भी हैं। देश मे रोजाना करीब पचास करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता हैं जिसमे चालीस फीसदी किसान खुद ही उपयोग कर लेता हैं और साठ फीसदी बाजार मे पहुँचता हैं। इसमें करीब एक तिहाई यानि करीब नौ

करोड़ लीटर दूध ही संगठित बाजार मे आ पाता हैं बाकि चालीस फीसदी दूध यानी की बीस करोड़ लीटर दूध असंगठित क्षेत्रो मे ही जाता हैं । दूध के कुछ उपयोग को छोड़कर अधिकतर उत्पादों का उपयोग बंद हैं जिससे दूध की कीमते गिरी हैं । दूध के किसानो को प्रतिदिन दो सौ करोड़ का नुकसान हो रहा हैं । अनुमान हैं की पूरी लाकबंदी मे करीब आठ हजार करोड़ का नुकसान होगा। कृषि से सम्बंधित दूसरे उत्पादों की कीमतों मे कमी आयी हैं । कृषि आय नकारात्मक स्तर पर पहुंच गयी हैं । कोरोना संकट से कृषि कारोबार लगभग बंदी के कगार पर हैं ।आई ऐल ओ के मुताबिक अनौपचारिक क्षेत्र की करीब चालीस करोड़ आबादी ग्रामीण इलाको मे काम करती हैं, आज यह आबादी गंभीर रोजगार संकट का सामना कर रही हैं । अगर कुछ नहीं हुआ तो ये गरीबी के दुश्चक्र मे फस जायेगे जिसके गंभीर परिणाम होंगे । भारत की सत्तर फीसदी आबादी मांसाहारी हैं और करीब दो करोड़ लोग पशु प्रोटीन सेगमेंट मे कार्यरत हैं । मांसाहारियों के लिए पशु प्रोटीन का सबसे बढ़ा जरिया हैं । कोरोना संकट से सबसे ज्यादा नुकसान इस क्षेत्र को हुआ हैं । पोल्ट्री किसान हर महीने दो किलो वजन वाले पचास करोड़ चिकन तैयार करते हैं ।किसानो के लिए उत्पादन लागत अस्सी रूपये किलो हैं जबकि अब दाम और गिर गया हैं ।अफवाह और सच्चाई के बीच इसका बाजार बिलकुल बंद हो गया हैं । यह दिवालिया होने के कगार पर हैं । किसान मांश बेच नहीं पा रहे हैं और मुर्गियों को खिलाने के लिए चारा नहीं हैं । आठ हजार करोड़ से अधिक के नुकसान की संभावना की गयी हैं । मछली पालन मे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो करोड़ के करीब लोग रोजगार मे लगे हैं । अस्सी से अधिक देशो मे इसका निर्यात होता हैं और बीस फीसदी से अधिक हिस्सेदारी कृषि निर्यात मे हैं लेकिन आज यह नुकसान मे हैं । सरकार ने लाकडाउन के दूसरे चरण मे अनुमति दी हैं लेकिन प्रतिबंधों के चलते यह अभी संकट मे हैं ।अप्रैल और मई मे सबसे अच्छी फिशिंग होती हैं लेकिन अभी भी नौ अरब की फिशिंग बंद हैं । गुजरात और अन्य जुड़े प्रदेशो मे अठ्ठाइस हजार से अधिक बोट अभी भी किनारे कड़ी हैं जो बोट पर काम करने वाले मजदूरों का इंतजार कर रही हैं ।

लाकडाउन से भारतीय उद्योग काफी प्रभावित हुए हैं । घरेलु और वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने आर्थिक विकास मे भारी गिरावट की आशंका जताई हैं ।अनुमान लगाया गया है की आर्थिक विकास दर तीन दशक के सबसे निचले पायदान पर पहुंच सकता हैं । एक अनुमान है की मार्च अंत और अप्रैल की प्रथम सप्ताह मे पच्चीस फीसदी के साथ बेरोजगारी दर चरम पर होगी । कपडा उद्योग पर अगले कुछ महीनो तक बुरा असर बना रहेगा । चीन मे लाकडाउन होने से कृत्रिम धागो का आयत हुआ महंगा जिससे तैयार माल की कीमते बढ़ने की पूरी सम्भावना व्यक्त की गयी हैं । इससे वस्त्र उद्योग मे देश से बारह फीसदी का गिरावट हो सकता हैं । निर्यात रुकने से धागो के उत्त्पादन मे गिरावट । घरेलु एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध से बड़े पैमाने पर यात्रायें रद्द । विदेशी पर्यटक के आगमन पर प्रतिबन्ध से अनुमानित बयासी हजार करोड़ का नुकसान संभावित हैं । उड्डयन और पर्यटन मे पाबन्दी से छोटी तनख्वाह और छोटे कर्मचारियों की छटनी का जबरदस्त अंदेशा हैं । कोरोना संकट से वाहन और पार्ट्स उद्योगों मे भी उत्त्पादन रुका । इससे नकदी का संकट और वाहनों की निजी खरीद काफी स्तर तक प्रभावित और वैश्विक मंदी से निर्यात पर बुरा असर । रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग भी गिरावट का शिकार हैं । वैश्विक मांग और पूर्ति के आभाव से भारतीय निर्यात पूरी तरह प्रभावित । रीयल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र भी इस संकट से नहीं उबर सका । सिम्मेंट और इस्पात सहित कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होने से अधिकतर परियोजनाएं बंद । करीब तीस से चालीस फीसदी रोजगार घटने की आशंका । विश्लेषकों द्वारा निवेशकों के मुँह मोड़ने की भी आशंका की गयी हैं ।

CMIE के मुताबिक, लॉकडाउन की वजह से लोगों की आवाजाही और सामान की ढुलाई में रुकावट आई। इसके चलते **16** मई, **2021** को खत्म हफ्ते हर **10,000** वर्कर पर बेरोजगारों की संख्या **1,450** पर पहुंच गई थी। **23** मई को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी दर बढ़कर **14.7%** यानी **1,470** प्रति **10,000** तक पहुंच गई।बेरोजगारी को सरकार की नजर से देखें तो उसके पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (**PLFS**) डेटा के मुताबिक, **2017-18** में बेरोजगारी दर **45** साल के सबसे ऊपरी लेवल **6.1%** तक पहुंच गई थी। यानी, उस साल हर **10,000** वर्कर में **610** बेरोजगार थे, लेकिन अगले साल यानी **2018-19** में उनका आंकड़ा घटकर **5.8% (580** प्रति **10,000)** पर आ गया। अगले साल यानी **2020-21** में कोविड के चलते स्थिति बिगड़ने और बेरोजगारी दर में खासा उछाल आने के आसार हैं। देश में रोजगार और बेरोजगारी दर के अहम संकेतकों के बारे में अनुमान लगाने के लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (**NSO)** अप्रैल **2017** से **PLFS** कर रहा है। **ILO** के डेटाबेस के मुताबिक, **2008** में हर **10,000** वर्कर में **536** बेरोजगार थे, जिनकी संख्या **2010** में **565** पर पहुंच गई। लेकिन, **2013** से **2019** के बीच इसमें लगातार गिरावट का रुझान बना रहा। **2013** में बेरोजगारी **567** वर्कर प्रति **10,000** से **2019** में **527** पर आ गई लेकिन **2020** में बेरोजगारों की संख्या तेज उछाल के साथ **711** पर पहुंच गई **।**

संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके आंकड़े काफी चौकाने वाले हैं। दरअसल, इस रिपोर्ट में कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में हुई प्रगति और विकास बुरी तरह से बाधित हुआ है। इसमें कहा गया है कि इस महामारी ने पिछले पांच वर्षों के दौरान विश्व ने जो मुकाम हासिल किया उसको भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की इस रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि फिलहाल इस संकट से जल्द ही बाहर आने के काफी कम आसार दिखाई दे रहे हैं। इस महामारी ने करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन ली है I बुधवार को जारी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की ये रिपोर्ट बताती है कि इस संकट से पूरी दुनिया में बेरोजगारों की संख्या बढ़कर **20** करोड़ **50** लाख हो जाएगी। इसकी वजह से गरीबों की संख्या में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। इस रिपोर्ट में चौकाने वाले तथ्य यहां पर ही खत्म नहीं होते है, बल्कि इसमें कहा गया है कि रोजगार के अवसरों में होने वाली बढ़ोतरी आने वाले दो वर्षों में भी इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस महामारी की वजह से अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे, दो अरब श्रमिक जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुए हैं। इस रिपोर्ट का एक और चौकाने वाला तथ्य ये भी है कि वर्ष **2019** के मुकाबले, **10** करोड़ **80** लाख अतिरिक्त श्रमिक अब गरीब या बेहद गरीब की श्रेणी में आ गए हैं। संगठन का अनुमान है कि वर्ष **2022** तक वैश्विक बेरोजगारी बढ़कर **20** करोड़ **50** लाख हो जाएगी, जो वर्ष **2019** की में **18** करोड़ **70** लाख थी। आईएलओ ने **164** पन्नों की ये रिपोर्ट विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य: रूझान **2021"** नाम से जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों करोड़ों महिलाओं, युवाओं पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा है और समाज में असमानता की खाई भी बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए **2020** में रोजगार के अवसरों में पांच फीसद, पुरुषों के लिए चार फीसदी की गिरावट आई है। इस महामारी ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में हुई बीते पांच साल की प्रगति को भी रोक दिया है। यदि विश्व में ये महामारी नहीं आई होती तो तीन करोड़ नई नौकरी पैदा हो सकती थी। इस महामारी की वजह से कई छोटे व्यवसाय बंद हो गए और करोड़ों लोग आर्थिक रूप से विभिन्न परेशानियों से जूझ रहे हैं। वैश्विक संकट से पैदा रोजगार की खाई **2021** में **7.5** करोड़ तक पहुंच जाएगी और **2022** में यह **2.3** करोड़ होगी । रोजगार और कामकाजी घंटे में कमी से बेरोजगारी का संकट उच्च स्तर पर पहुंचेगा.रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘इसके फलस्वरूप **2022** में वैश्विक स्तर पर **20.5** करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है जबकि **2019** में **18.7** करोड़ लोग बेरोजगार थे । इस तरह बेरोजगारी दर **5.7** प्रतिशत है. कोविड-**19** संकट अवधि को छोड़कर यह दर इससे पहले **2013** में थी ।

निष्कर्ष :

हम कह सकते है की आयातित कोरोना संकट बुरी तरह से भारत मे अपना घर बनाने की फ़िराक मे हैं हालाँकि सरकार ,समाज के जागरूक लोग और समाज की संस्थाए पूरी तरह से संकट से बचने हेतु प्रयास कर रही हैं टीकाकरण और दुरी ही बचाव हैं के मूल मंत्र का पालन कर रही हैं और इनका उबरना भारतीय समाज की मजबूती के लिए अति आवश्यक भी हैं ।

सन्दर्भ :

1. Hui, David S; Azhar, Esam E; Madani, Tariq A; Ntoumi, Francine; Kock, Richard; Dar, Osman; Ippolito, Giuseppe; Mchugh, Timothy D; Memish, Ziad A (14 january 2020) "The continuing epidemic threat of novel coronaviruses to global health – the latest novel coronavirus outbreak in Wuhan, China" International Journal of Infectious Diseases
2. Gettleman, Jeffrey; Schultz, Kai (24 March 2020) "Modi Orders 3-Week Total Lockdown for All 1.3 Billion Indians" The New York Times
3. सरदाना, विजय (2020):अफवाहों और लाकडाउन से बेहाल पोल्ट्री -डेरी सेक्टर, इंडिया टुडे, 4 मई 2020.
4. दैनिक भास्कर (2020):अनुमति मिली पर न मजदुर न खरीदार 9 अरब की फिशिंग ठप, 23 अप्रैल 2020.
5. https://www.bhaskar.com/business/news/in-2020-the-unemployment-rate-in-india-is-the-highest-in-3-decades-ilo-128538525
6. https://www.jagran.com/world/america-no-recovery-in-global-jobs-market-from-pandemic-until-at-least-2023-ilo-report-21703833.html